

The Uttar Pradesh State Legal Services

Authority Rules, 1996

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987) and in consultation with the Chief Justice, the Governor is pleased to make the following rules:

1. Short title and commencement

1. These rules may be called the Uttar Pradesh Legal Services Authority Rules, 1996.
2. They shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions- In these rules unless the context otherwise requires -

- (a) 'Act' means the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act. No. 39 of 1987);
- (b) 'Chief Justice' means Chief Justice of the High Court;
- (c) 'Executive Chairman' means Executive Chairman of the State Authority;
- (d) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;
- (e) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;
- (f) 'High Court' means the High Court of Judicature at Allahabad;
- (g) 'Member' means member of the State Authority or member of the High Court Legal Services Committee or member of a District Authority or member of a Tehsil Legal Services Committee, as the case may be;
- (h) 'Member-Secretary' means Member-Secretary of the State Authority;
- (i) 'Section' means section of the Act;
- (j) 'Tehsil Legal Services Committee' means Taluk Legal Services Committee as defined in clause (k) of section 2.

3. Number, experience and qualifications of other members of the State Authority

1. Besides the Patron-in-Chief and the Executive

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय विभाग

अनुभाग-7

अधिसूचना

12 मार्च, 1996 ई0

सं. 123/सात-न्याय-7-96-45-90 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, 1987) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

नियमावली, 1996

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 कर्त जाएगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषायें - जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) से है,
- (ख) "मुख्य न्यायमूर्ति" का तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से है,
- (ग) "कार्यपालक अध्यक्ष" का तात्पर्य राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष से है,
- (घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,
- (ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,
- (च) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है,
- (छ) "सदस्य" का तात्पर्य यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण के सदस्य या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य या किसी जिला प्राधिकरण के सदस्य या किसी तहसील

Chairman, the State Authority shall have not more than seventeen members including Member-Secretary.

2. In addition to members nominated under sub-rule (3), the State Authority shall consist of the following other members-

(a) Advocate General, Uttar Pradesh;
(b) Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh;

(c) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Finance Department;

(d) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Judicial Department;

(e) Director General of Police, Uttar Pradesh;

(f) Chairman, Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(g) Two District Judges nominated by the Government in consultation with the Chief Justice;

(h) Chairman, Bar Council, Uttar Pradesh;

* (i) Registrar General High Court, Allahabad;

(j) D.G.P. (Prosecution)

(k) Director, Social Welfare Department, U.P.

(l) Principal Secretary or Secretary to Govt. in the information & Public Relating Department;

(m) Director, Women Welfare Department, U.P.

3. The Government may, in consultation with the Chief Justice, nominate seven other members of the State Authority from amongst the persons possessing the experience and qualifications specified in sub-rule (4).

4. A person shall not be qualified to be nominated as member of the State Authority, unless he is-

(a) an eminent Social Worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections

विधिक सेवा समिति के सदस्य से है,

(ज) "सदस्य-सचिव" का तात्पर्य राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव से है,

(झ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है,

(ञ) "तहसील विधिक सेवा समिति" का तात्पर्य धारा 2 के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित तालुक विधिक सेवा समिति से है,

3. राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हतायें-

(1) मुख्य संरक्षक और कार्यपालक अध्यक्ष के अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण में सदस्य सचिव को सम्मिलित करते हुए सत्रह से अनधिक सदस्य होंगे।

(2) उपनियम (3) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे-

(क) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

(ख) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

(ग) सरकार के वित्त विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव।

(घ) सरकार के न्याय विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव।

(ङ) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

(च) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग।

(छ) मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो जिला न्यायाधीश।

(ज) अध्यक्ष, बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश।

* (झ) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(ञ) पुलिस महानिदेशक, (अभियोजन)।

(ट) निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

(ठ) सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव,

(ड) निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

3. सरकार, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अनुभव और अर्हताएं रखने वाले राज्य प्राधिकरण

of the society, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, Children, rural and urban labour;

- (b) an eminent person in the field of law; or
- (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

4. Powers and functions of the Member-Secretary-

The powers and functions of the Member-Secretary shall be-

- a. to provide legal services to a person entitled to legal services under the Act;
- b. to work out modalities of the Legal Services Schemes and Programmes approved by the State Authority and ensure their effective monitoring and implementation;
- c. to exercise the powers in respect of Administrative House-keeping, Finance and Budget matters as Head of the Department in the Government;
- d. to manage the properties, records and funds of the State Authority;
- e. to maintain true and proper accounts of the State Authority including periodical checking and auditing in respect thereof;
- f. to prepare Annual Income and Expenditure Account and Balance Sheet of the State Authority;
- g. to liaise with the Social Action Groups and District Authority and Tehsil Legal Services Committee;
- h. to maintain upto date and complete statistical information including progress made in the implementation of various Legal Services Programmes from time to time;
- i. to process proposal for financial assistance and issue Utilisation Certificates thereof;
- j. to organise various Legal Services programmes approved by the State Authority and to convene Meetings/Seminars and Workshops connected with Legal Services Programmes and to prepare reports of such Meeting/Seminars/Workshops and to ensure

के सात अन्य सदस्यों का नाम निर्दिष्ट कर सकती है।

4. कोई व्यक्ति राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किये जाने के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह-

- (क) समाज के कमजोर वर्गों के, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बच्चे, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी सम्मिलित हैं, उत्थान में लगा हुआ कोई प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता न हो,
- (ख) विधिक के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति न हो, या
- (ग) विधिक सेवा स्कीम के कार्यान्वयन में विशेष रूप से हितबद्ध कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो।

(4) सदस्य-सचिव की शक्तियां और कृत्य - सदस्य-सचिव की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे-

- (क) अधिनियम के अधीन विधिक सेवाओं के हकदार किसी व्यक्ति को विधिक सेवाएं प्रदान करना,
- (ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विधिक सेवा स्कीमों और कार्यक्रमों की रूपात्मकता की परिकलन और उनके प्रभावी अनुश्रवण और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना,
- (ग) सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक गृह प्रबन्ध, वित्त और आय-व्ययक के सम्बन्ध में शक्ति का प्रयोग करना,
- (घ) राज्य प्राधिकरण की सम्पत्तियों, अभिलेखों और निधियों का प्रबन्ध करना,
- (ङ) राज्य प्राधिकरण के लेखों का जिसमें उनकी सामयिक लेखा परीक्षा और जांच भी सम्मिलित है, सही और उचित रख-रखाव करना,
- (च) राज्य प्राधिकरण का वार्षिक आय और व्यय लेखा और तुलन-पत्र तैयार करना,
- (छ) सामाजिक कार्य समूह और जिला प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा समिति से सम्पर्क करना,
- (ज) अद्यतन और पूर्ण सांख्यिकी सूचना का जिसमें समय-समय पर विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों में की गयी प्रगति भी सम्मिलित है, रख-रखाव करना,
- (झ) वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावों का प्रसंस्करण करना और उनके उपभोग प्रमाण-पत्रों को निर्गत करना,

- follow-up action thereon;
- k. to produce video/documentary films, publicity material, literature and publications to inform general public about the various aspects of the Legal Services Programmes;
 - l. to lay stress on the resolution of rural disputes and to take extra measure to draw schemes for effective and meaningful legal services for settling rural disputes at the door steps of the rural people;
 - m. to perform such of the functions as are assigned to him under the Schemes framed under clause (b) of section 4;
 - n. to exercise effective control over the functioning of the High Court Legal Services Committee, the District Authority and the Tehsil Legal Services Committee and to provide them guidance; and necessary assistance in carrying out the programmes and schemes framed under the Act;
 - o. to exercise such power and perform such functions and duties as may be assigned to him by the Executive Chairman; and
 - p. to perform such other functions as may be expedient for efficient discharge of the functions of the State Authority.

5. Services conditions of the Executive Chairman-

The Service conditions of the Executive Chairman in case of his being a retired Judge of the High Court shall be such as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.

6. Terms of office and other conditions of Members and Member-Secretary of the State Authority-

1. The terms of office of members of the State Authority nominated under sub-rule (3) of rule 3 shall be two years and such members shall be eligible for re-nomination.
2. A member of the State Authority nominated under sub-rule (3) of rule 3 may be removed by the Government, if in the opinion of the Government, it is not desirable to continue

- (अ) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन करना और विधिक सेवा कार्यक्रमों से सम्बन्धित बैठकें/सेमिनार और कार्यशाला का संयोजन करना और ऐसी बैठकों/सेमिनारों/कार्यशालाओं की रिपोर्ट तैयार करना, और उन पर की गयी कार्यवाही का अनुसरण सुनिश्चित करना,
- (ट) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सामान्य जनता को सूचित करने के लिए वीडियो/वृत्तचित्रों, प्रचार सामग्रियों, साहित्यों और प्रकाशनों को प्रस्तुत करना,
- (ठ) ग्रामीण विवादों के संकल्पों पर जोर डालना और ग्रामीणों के लिए उनके द्वार पर ग्रामीण विवादों को निपटाने के लिए प्रभावी और अर्थपूर्ण विधिक सेवाओं की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त अध्यापनायक करना,
- (ड) ऐसे कृत्यों का, जो धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन बनायी गई स्कीमों के अधीन उसे सौंपे गये हों, सम्पादन करना,
- (ढ) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा समिति के कृत्यों पर प्रभावी नियन्त्रण रखना और अधिनियम के अधीन बनाए गये कार्यक्रमों और स्कीमों को क्रियान्वित कराने में उन्हे मार्ग-दर्शन और आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- (ण) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का सम्पादन करना जो कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जायें और
- (त) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करना जो राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए समाचीन हों।

5. कार्यकारी अध्यक्ष की सेवा शर्तें - उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश होने की दशा में कार्यकारी अध्यक्ष की सेवा शर्तें वहीं होंगी जैसे सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अवधारित की जायें।

6. राज्य प्राधिकरण के सदस्यों एवं सदस्य सचिव की पदावधि और अन्य शर्तें - (1) नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी और ऐसे सदस्य पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 343 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1019/VII-Nyaya-7-2003-45/90T.C. (Kha), dated June 30, 2003:

No. 1019/VII-Nyaya-7-2003-45/90T.C. (Kha)

Dated Lucknow, June 30, 2003

IN exercise of the powers conferred by section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no. 39 of 1987) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. X of 1897) and in consultation with the Chief Justice, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996.

**THE UTTAR PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
(FIRST AMENDMENT) RULES, 2003**

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Legal services authority (First Amendment) Rules, 2003.

Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in official Gazette.

2. In the Uttar Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules, in rule 3, for sub-rules (1) and (2) set out in Column-I below, the sub-rules as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

Amendment of rule-3

COLUMN-I

COLUMN-II

(Existing sub-rule)

(Sub-rule as hereby substituted)

(1) Besides the Patron-in-Chief and the Executive Chairman, the State Authority shall have not more than seventeen members including Member-Secretary.

(1) Besides the Patron-in-Chief and the Executive Chairman, the State Authority shall have not more than twenty-two members including Member-Secretary.

(2) In addition to members nominated under sub-rule (3), the State Authority shall consist of the following other members-

(2) In addition to members nominated under sub-rule (3), the State Authority shall consist of the following other members-

(a) Advocate General, Uttar Pradesh;

(a) Advocate General, Uttar Pradesh;

(b) Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh;

(b) Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh;

(c) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Finance Department;

(c) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Finance Department;

(d) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Judicial Department;

(d) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Judicial Department;

(e) Director General of Police, Uttar Pradesh;

(e) Director General of Police, Uttar Pradesh;

(f) Chairman, Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(f) Chairman, Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(g) Two District Judges nominated by the Government in consultation with the Chief Justice;

(g) Two District Judges nominated by the Government in consultation with the Chief Justice;

COLUMN-I*(Existing sub-rule)*

(h) Chairman, Bar Council, Uttar Pradesh;

COLUMN-II*(Sub-rule as hereby substituted)*

(h) Chairman, Bar Council, Uttar Pradesh;

(i) Registrar General, High Court, Allahabad;

(j) Director General of Police (Prosecution);

(k) Director, Social Welfare Department, Uttar Pradesh;

(l) Principal Secretary or Secretary as the case may be, to the Government in the Information and Public Relations Department;

(m) Director, Women Welfare Department, Uttar Pradesh;

Amendment of rule 6

3. In the said rules, in rule 6, for sub-rule (1) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I*(Existing sub-rule)*

(1) The terms of office of members of the State Authority nominated under sub-rule (3) of rule 3 shall be two years and such members shall be eligible for renomination.

COLUMN-II*(Sub-rule as hereby substituted)*

(1) The terms of office of members of the State Authority nominated under sub-rule (3) of rule 3 shall be two years and such members shall be eligible for renomination :

Provided that a nominated members shall continue to be the member of the State Authority after the expiry of his term till his successor is nominated under sub-rule (3) of the rule 3.

Amendment of rule 11

4. In the said rules, rule 11, for sub-rules (1) and (2) set out in Column-I below, the sub-rules as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I*(Existing sub-rules)*

(1) A District Authority shall have not more than twelve other members.

(2) In addition to members nominated under sub-rule (3), a District Authority shall consist of the following other members :-

(a) District Magistrate;

(b) Senior Superintendent of Police, or the case may be;

(c) Chief Judicial Magistrate;

(d) District Government Counsel (Civil);

COLUMN-II*(Sub-rules as hereby substituted)*

(1) A District Authority shall have not more than sixteen other members.

(2) In addition to members nominated under sub-rule (3), a District Authority shall consist of the following other members :-

(a) District Magistrate;

(b) Senior Superintendent of Police, as the case may be;

(c) Chief Judicial Magistrate;

(d) District Government Counsel (Civil);

COLUMN-I

(Existing sub-rule)

(e) District Government Counsel (Criminal);

(f) District Government Counsel (Revenue);

Amendment of rule 11(3)

The Government may, in consultation with the Chief Justice, nominate six other members of a District Authority from amongst the persons possessing the experience and qualification specified in sub-rule (4).

COLUMN-II

(Sub-rule as hereby substituted)

(e) District Government Counsel (Criminal);

(f) District Government Counsel (Revenue);

(g) Chief Medical Officer;

(h) District Social Welfare Officer;

(i) District Information Officer;

(j) District Senior Prosecution Officer.

The Government may, in consultation with the Chief Justice, nominate six other members of a District Authority from amongst the experience and qualification specified in sub-rule (4).

The term of office of members shall continue after 2 years till successor is nominated.

amendment of rule 14(3)

The Government may, in consultation with the Chief Justice, nominate three other member of a Tehsil Legal Services committee from amongst the persons possessing the qualifications and experience specified in sub-rule (4).

The Government may, in consultation with the Chief Justice, nominate three other member of a Tehsil Legal Services committee from amongst the persons possessing the qualifications and experience specified in sub-rule (4).

~~The term of office of members shall continue after 2 years till successor is nominated.~~

Distt. Authority

5. In the said rules, 17 set out in Column-I below, the sub-rule set out in Column-II shall be substituted, namely :-

Amendment of rule-17

COLUMN-I

(Existing sub-rule)

Experience and qualification for other persons under sub-section (4) of section 19 :

A person shall not be qualified to be included in the Bench of Lok Adalat, unless he is:-

(a) an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the Society, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children, Rural and Urban labour, or

COLUMN-II

(Sub-rule as hereby substituted)

Experience and qualification for other persons under sub-section (4) of section 19 :

A person shall not be qualified to be included in the Bench of Lok Adalat, unless he is:-

(a) an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the Society, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children, Rural and Urban labour, or

COLUMN-I	COLUMN-II
<i>(Existing sub-rule)</i>	<i>(Sub-rule as hereby substituted)</i>
(b) A lawyer of standing or	(b) A lawyer of standing or
(c) A person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes and Programmes;	(c) A person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes and Programmes; or
	(d) Revenue Officer or other a Adjudicatory Authority.

By order,
A. B. SHUKLA,
Prमुख Sachiv.

him as member.

3. If any vacancy occurs due to death or otherwise in the office of member of the State Authority, it shall be filled in the manner provided for in these rules for the residue of the term of his predecessor.

4. All members shall be entitled to payment of travelling allowance and daily allowance in respect of journey performed in connection with the work of the State Authority and shall be paid by the State Authority in accordance with the regulations made under section 29-A.

Explanation- If a member is a Government employee, he shall be entitled to only one set of travelling allowance and daily allowance from his parent department or from the State Authority.

The Member Secretary shall be the whole time employee and shall hold office for a term not exceeding five year, which may be extended for a further period not exceeding one year by the Government in consultation with Chief Justice.

6. In all matters, like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements, disciplinary matters and other conditions of service, the Member-Secretary shall be governed by the rules applicable to the members of the Uttar Pradesh Higher Judicial Service. The Member-Secretary shall be on deputation to the State Authority.

Number of officers and other employees of the State Authority-

1. The number of officers and other employees including Secretary II, Officers-on Special Duty and Deputy Secretary of the State Authority shall be such as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.

2. The number of officers and other employees including Secretary II, Officer-on-Special Duty and Deputy Secretary of the State Authority shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix A.

(2) नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के किसी सदस्य को सरकार द्वारा हटाया जा सकता है यदि सरकार की राय में उसे सदस्य के रूप में बनाये रखना अपेक्षित न हो।

(3) यदि मृत्यु हो जाने के कारण या अन्यथा राज्य प्राधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाय तो उसे इस नियमावली में दी गई रीति से पूर्वाधिकारी का अवशिष्ट अवधि के लिए भरा जाएगा।

(4) राज्य प्राधिकरण के कार्य के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिए सभी सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे और उनका भुगतान धारा 29-क के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- यदि कोई सदस्य सरकारी सेवक है तो वह अपने मूल विभाग से या राज्य प्राधिकरण से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का मात्र एक समुच्चय पाने का हकदार होगा।

(5) सदस्य सचिव पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और जो पांच वर्ष से अनधिक पदावधि के लिए जो मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से सरकार द्वारा एक वर्ष से अनधिक की अग्रतर अवधि के लिए बढ़ाया जा सकती है, पद धारण करेगा।

(6) सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन और भत्ते, प्रसुविधा और हकदारी, अनुशासनात्मक विषयों और सेवा की अन्य शर्तों जैसे सभी मामलों में सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा पर लागू नियमों द्वारा शासित होगा। सदस्य सचिव राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होगा।

(7) राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या - (1) राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सचिव दो, विशेष कार्य अधिकारी और उपसचिव को सम्मिलित करते हुए संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अवधारित की जाए।

(2) राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की, सचिव-दो, विशेष कार्य अधिकारी और उप-सचिव को सम्मिलित करते हुए संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन के आदेश न दिए जाएं, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

(3) उत्तर प्रदेश विधिक सहायता और परामर्श बोर्ड में इस

3. All the Officers and other employees including Secretary II, Officer-on Special Duty and Deputy Secretary working immediately before the commencement of these rules, in the Uttar Pradesh Legal Aid and Advice Board shall, on such commencement, be the officers and other employees of the State Authority.

8. Conditions of service, pay and allowances of the Officers and other employees of the State Authority-

1. The Officers and other employees of the State Authority other than Secretary II, Officer-on Special Duty and Deputy secretary shall be entitled to such pay and allowances as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.
2. The scales of pay at the time of the commencement of these rules are as given in the Appendix A.
3. The officers and other employees of the State Authority shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.
4. Secretary II and Officer on Special Duty shall be appointed, in consultation with the Chief Justice, from amongst persons belonging to the Uttar Pradesh Higher Judicial Service for a term not exceeding five years.
5. Deputy Secretary shall be appointed, in consultation with the Chief Justice, from amongst persons belonging to the Uttar Pradesh Nyayik Sewa not below the Rank of Civil Judge (Senior Division).
6. In all matters, like age of retirement pay and allowances, benefits and entitlements disciplinary matters and other conditions of service Secretary II, Officer-on-Special Duty and Deputy Secretary shall be governed by the rules applicable to the service to which they belong. The Secretary II, Officer-on-Special duty and Deputy Secretary shall be on deputation to the State Authority.
7. Until the terms and conditions of service of officers and other employees of the State

नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व कार्यरत सचिव-दो, विशेष कार्य अधिकारी और उप सचिव को सम्मिलित करते हुए सभी अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी, ऐसे प्रारम्भ पर, राज्य प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे।

8. राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें-

(1) सचिव-दो, विशेष कार्य अधिकारी और उप सचिव से भिन्न राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अवधारित किए जायें।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान परिशिष्ट "क" में दिया गया है

(3) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और प्रसुविधाओं के हकदार होंगे जैसी सरकार द्वारा न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर व्यवस्थित की जाय।

(4) सचिव-दो और विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के व्यक्तियों में से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जायेगी।

(5) उपसचिव की नियुक्ति मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी जो सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से निम्न श्रेणी का न हो।

(6) सेवा निवृत्त की आयु, वेतन और भत्ते, प्रसुविधा और हकदारी, अनुशासनात्मक मामलों और अन्य सेवा शर्तों जैसे सभी मामलों में सचिव-दो, विशेष कार्य अधिकारी और उपसचिव उस सेवा की नियमावली से शासित होंगे जिससे वे सम्बन्धित हैं। सचिव-दो, विशेष कार्य अधिकारी और उप सचिव राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होंगे।

(7) सचिव-दो, विशेष कार्य अधिकारी और उप सचिव से भिन्न, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबन्धन जब तक विहित नहीं होता है तब तक उनकी अर्हताएं, भर्ती की प्रक्रिया और अन्य सेवा शर्तें जिसमें

Authority other than the Secretary II, Officer-on-Special Duty and Deputy Secretary are prescribed, their qualifications, procedure for recruitment and other conditions of service including disciplinary matters, leave provident fund and other matters shall be the same as that of the officers and employees of similar category in the Government and rules relating thereto shall mutatis mutandis apply.

9. Experience and qualifications of the Secretary to the High Court Legal Services Committee-

A person shall not be qualified for appointment as Secretary to the High Court Legal Services Committee unless he is an officer of the High Court not below the Rank of Joint Registrar, belonging to the Uttar Pradesh Higher Judicial Service.

10. Numbers of Officers and other employees of the High Court Legal Services Committee and their conditions of service, pay and allowances-

1. The number of officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be such as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.
2. The number of officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix B.
3. All the officers and other employees other than the Secretary, working immediately before the commencement of these rules, in the High Court Legal Aid and Advice Committee, shall, on such commencement be the officers and employees of the High Court Legal Services Committee.
4. The Officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be entitled to such pay and allowances as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.
5. The scales of pay at the time of

अनुशासनात्मक मामले, छुट्टी भविष्य निधि और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं, वही होगी जैसी कि सरकार में समान श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों की है और उनसे सम्बन्धित नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

9. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हताएं

कोई व्यक्ति तब तक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के संयुक्त निबंधक से निम्नवार श्रेणी का अधिकारी न हों।

10. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें वेतन और भत्ते

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या ऐसी होगी जैसी मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "ख" में दी गयी है।

(3) उच्च न्यायालय विधिक सहायता और परामर्श समिति में, इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व कार्यरत, सचिव से भिन्न सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी प्रारम्भ पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और कर्मचारी होंगे।

(4) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जैसे सरकार द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर अवधारित की जाए।

(5) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट "ख" दिये गए हैं।

commencement of these rules are as given in the Appendix B.

6. Until the terms and conditions of service of officers and other employees of the High Court Legal Services Committee are prescribed, their qualifications, procedure for recruitment and other conditions of service including disciplinary matters, leave, Provident Fund and other matters shall be the same as that of the officers and employees of similar category in the Government and rules relating thereto shall *Mutatis Mutandis* apply.
7. The officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.

11. Number, experience and qualifications of other members of District Authority-

1. A District Authority shall have not more than twelve other members.
2. In addition to members nominated under sub-rule (3), a District Authority shall consist of the following other Members-
 - (a) District Magistrate;
 - (b) Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police, as the case may be;
 - (c) Chief Judicial Magistrate;
 - (d) District Government Counsel (Civil);
 - (e) District Government Counsel (Criminal);
 - (f) District Government Counsel (Revenue).

* (g) Chief Medical Officer;

(h) District Social Welfare Officer;

(i) District Information Officer;

(j) District Senior Prosecution Officer.
3. The Government may, in consultation with the Chief Justice, nominate six other members of a District Authority from amongst the persons possessing the experience and qualifications specified in sub-rule (4).

(6) जब तक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें विहित न हो जाएं, उनकी अर्हताएं, भर्ती की प्रक्रिया और अन्य सेवा की शर्तें, जिसमें अनुशासनात्मक मामले, छुट्टी भविष्य निधि और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं, ऐसी होंगी जैसी कि सरकार में समान श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों की हैं और उनसे संबंधित नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(7) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी को ऐसी अन्य सुविधाएं, भत्ते और प्रसुविधा प्राप्त होंगी जैसी सरकार द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर अवधारित की जाए।

11. जिला प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएँ

(1) किसी जिला प्राधिकरण में बारह से अनधिक अन्य सदस्य होंगे।

(2) उपनियम (3) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त किसी जिला प्राधिकरण में निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे।

- क. जिला मजिस्ट्रेट
- ख. यथास्थिति ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक,
- ग. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
- घ. जिला सरकारी काउन्सेल (सिविल)
- ङ. जिला सरकारी काउन्सेल (दाण्डिक),
- च. जिला सरकारी काउन्सेल (राजस्व),
- * छ. मुख्य चिकित्साधिकारी,
- ज. जिला समाज कल्याण अधिकारी,
- झ. जिला सूचना अधिकारी,
- ञ. जिला ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी।

(3) सरकार, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किसी जिला प्राधिकरण के छः अन्य सदस्यों को उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अनुभव और अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट कर सकती हैं।

4. A person shall not be qualified to be nominated as member of a District Authority, unless he is-

- (a) an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the society, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children, Rural and urban labour;
- (b) an eminent person in the field of law; or
- (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

12. Number of Officers and other employees of District Authority-

1. The number of officers and other employees of a District Authority shall be such as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.
2. The number of officers and other employees of a District Authority shall, untill orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in Appendix C.
3. All the officers and other employees working, immediately before the Commencement of these rules, in a District Legal Aid and Advice Committee, shall on such commencement, be the officers and employees of the District Authority.

13. Conditions of service, pay and allowances of the officers and other employees of District Authority-

1. The officers and other employees of the District Authority shall be entitled to such pay and allowances as may be determined by the Government, from time to time in consultation with the Chief Justice.
2. The scales of pay at the time of the commencement of these rules are as given in Appendix C.
3. The officers and other employees of the District Authority shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be determined by the Government from time to time, in consultation with the Chief Justice.

(4) कोई व्यक्ति किसी जिला प्राधिकरण के सदस्य के रूप में तब तक नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह-

(क) कोई ऐसा प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो समाज के कमजोर वर्गों, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाएं, बच्चों, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी सम्मिलित हैं, के उत्थान में लगा हुआ हो, या

(ख) विधि के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति न हो, या

(ग) कोई ऐसा ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो जो विधिक सेवा स्कीम के कार्यान्वयन में विशेष रूप से हितबद्ध हो।

12. जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या

(1) जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या उतनी होगी जितनी समय-समय पर सरकार द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन किये जाने के आदेश न दिये जाएं जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट "ग" में दी गई है।

(3) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व किसी जिले में विधिक सहायता और परामर्श समिति में कार्यरत समस्त अधिकारी और कर्मचारी ऐसे प्रारम्भ पर जिला प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी होंगे।

13. जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें -

(1) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों को पाने के हकदार होंगे जैसा सरकार द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर अवधारित किये जायें।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट "ग" में दिये गए हैं।

(3) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधायें, भत्ते और अन्य प्रसुविधाओं को पाने के हकदार होंगे जैसे सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अवधारित किये जायें।

4. Until terms and conditions of service of officers and other employees of the District Authority are prescribed, their qualifications, procedure for recruitment and other conditions of service including disciplinary matter, leave, Provident Fund and other matters shall be the same as that of the officers and employees of a similar category in the Government and rules relating thereto shall *mutatis mutandis* apply.

14. Number, experience and qualifications of other members of Tehsil Legal Services Committee-

1. A Tehsil Legal Services Committee shall have not more than five members.
2. In addition to members nominated under sub-rule (3) a Tehsil Legal Services Committee shall consist of the following other members-
 - (a) Sub-Divisional Officer of the Tehsil;
 - (b) Senior most Gazetted Police Officer posted within the local limits of the Tehsil.
3. The Government may in consultation with the Chief Justice, nominate three other members of a Tehsil Legal Services Committee from amongst the persons possessing the qualifications and experience specified in sub-rule (4).
4. A person shall not be qualified to be nominated as member of a Tehsil Legal Services Committee, unless he is -
 - a) an eminent social worker who permanently resides within the local limits of the Tehsil concerned and is engaged in the upliftment of the weaker sections of the society, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children Rural and Urban labour;
 - (b) an eminent person in the field of law; or
 - (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

15. Number of officers and other employees of Tehsil Legal Services Committee-

1. The number of officer and other employees

(4) जब तक जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें विहित नहीं होती हैं, उनकी अर्हताएं, भर्ती की प्रक्रिया और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें अनुशासनात्मक मामले, अवकाश, भविष्य निधि और अन्य विषय सम्मिलित हैं, वहीं होंगी जैसी कि सरकारी सेवा में उसी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों की है और उनसे सम्बन्धित नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

14. तहसील विधिक सेवा समिति के अन्य सदस्यों की संख्या, उनका अनुभव और उनकी अर्हताएं

(1) किसी तहसील विधिक सेवा समिति में पांच से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त तहसील विधिक सेवा समिति में निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे-

क. तहसील का उपखण्ड अधिकारी,

ख. तहसील की स्थानीय सीमाओं में तैनात ज्येष्ठतम राजपत्रित पुलिस अधिकारी,

(3) सरकार मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से तहसील विधिक सेवा समिति के तीन अन्य सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकती है।

(4) कोई व्यक्ति तहसील विधिक सेवा समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह-

(क) कोई प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो सम्बन्धित तहसील की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थायी रूप से निवास करता हो और समाज के कमजोर वर्गों के जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाएं, बच्चे, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी सम्मिलित हैं, उत्थान में लगा हुआ हो,

(ख) विधि के क्षेत्र में प्रख्यात न हो, या

(ग) कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो जो विधिक सेवा स्कीम के कार्यान्वयन में विशेष रूप से हितबद्ध हो।

15. तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या -

(1) किसी तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और

of a Tehsil legal Services Committee shall be such as may be determined by the Government, from time to time, in consultation with the Chief Justice.

2. The Officers and other employees of a Tehsil Legal Services Committee shall be entitled to such pay and allowances as may be determined by the Government from time to time, in consultation with the Chief Justice.
3. The Officers and other employees of a Tehsil Legal Services Committee shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be determined by the Government from time to time, in consultation with the Chief Justice.
4. Until terms and conditions of service of officers and other employees of Tehsil Legal Services Committee are prescribed, their qualifications, procedure for recruitment and other conditions of service including disciplinary matter, leave, Provident Fund and other matters shall be the same as that of the officers and employees of similar category in the Government and rules relating thereto shall *mutatis mutandis* apply.

16. Upper-limit of annual income of a person entitling him to Legal Services if the case is before court, other than the Supreme Court-

A person, whose annual income from all sources does not exceed rupees twelve thousands or such higher amount as may be determined by the Government, from time to time, if the case is before a Court other than the Supreme Court, shall be entitled to Legal Services under the Act.

17. Experience and qualifications for other persons under sub-section (4) of section 19-

A person shall not be qualified to be included in the Bench of Lok Adalat, unless he is-

- a. an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker section of the society, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, children rural and

अन्य कर्मचारियों की संख्या ऐसी होगी जैसी कि सरकार द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) किसी तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे जैसा कि सरकार द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर अवधारित किये जायें।

(3) तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और प्रसुविधाओं के हकदार होंगे जैसी कि सरकार द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर अवधारित की जाए।

(4) जब तक कि तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें विहित न की जाएं, उनकी अर्हताएं, भर्ती की प्रक्रिया और सेवा की अन्य शर्तें जिसमें अनुशासनात्मक मामले, अवकाश भविष्य निधि और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं, सरकार में समान श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के समान ही होंगी और उनसे सम्बन्धित नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

16. किसी व्यक्ति की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा जो उसे विधिक सेवाओं का हकदार ठहराती है, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में हो

कोई व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय सभी श्रोतों से पच्चीस हजार रुपये या ऐसी उच्चतर धनराशि जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, से न हो, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में हो, अधिनियम के अधीन विधिक सेवायें प्राप्त करने का हकदार होगा।

17. धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन अन्य व्यक्तियों के अनुभव और अर्हताएँ

कोई व्यक्ति लोक अदालत की पीठ में सम्मिलित किये जाने के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह-

(क) प्रख्यात समाज सेवी न हो जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण और शहरी मजदूरों को सम्मिलित करते हुए समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा हो, या

- urban labour; or
b. a lawyer of standing; or

- c. a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes and Programmes.

APPENDIX 'A'
[See Rules 7 (2) and 8 (2)]

Sl. No.	Name of Post	Number of Post	Scales of pay
1	2	3	4
1.	Secretary II	1	Scales of pay admissible to the members of the Uttar Pradesh Higher Judicial Service.
2.	Officer on Special Duty	1	Ditto.
3.	Deputy Secretary	2	Scale of pay admissible to Civil Judge (Senior Division)
4	Personnel Secretary	1	Rs. 2000-60-2300-E.B.--75-3200-100-3500
5	Personnel Assistant	3	Rs. 1640-60-2600-E.B.-75-2900
6	Stenographer	2	Rs. 1200-30-1560-E.B.-40-2040
7	Administrative Officer	1	Rs. 1640-60-2600-E.B.-75-2900
8-	Upper Division Assistant	3	Rs. 1350-30-1440-40-1800-E.B.-50-2200
9-	Accounts Clerk	1	Rs. 1200-30-1560-E.B.-40-2040
10-	Senior Clerk	1	Rs. 1200-30-1560-E.B.-40-2040
11-	Typist	2	Rs. 950-20-1150-E.B.-25-1500
12-	Junior Clerk	3	Rs. 950-20-1150-E.B.-25-1500
13-	Library Clerk	1	Rs. 950-20-1150-E.B.-25-1500
14-	Orderly/Peon	10	Rs. 750-12-870-E.B.-14-940
15-	Daftary/Machine Operator	1	Rs. 775-12-955-E.B.-14-1025
16-	Driver	3	Rs. 950-20-1150-E.B.-25-1500
17-	Sewak	1	Rs. 35.00 per day
18-	Sweeper-cum-Farrash	1	Rs. 500.00 per month fixed pay.

APPENDIX 'B'
[See Rules 10 (2) and 10 (5)]

Sl. No.	Name of Post	Number of Post	Scales of pay
1	2	3	4
1.	Clerk	2	Rs. 950-20-1150-E.B.-25-1500
2.	Orderly/Peon	2	Rs. 750-12-870-E.B.-14-940

APPENDIX 'C'
[See Rules 12 (2) and 13 (2)]

Sl. No.	Name of Post	Number of Post	Scales of pay
1	2	3	4
1.	Clerk	66	Rs. 950-20-1150-E.B.-25-1500
2.	Peon	66	Rs. 750-12-870-E.B.-14-940

ख. प्रतिष्ठा प्राप्त वकील न हो, या

ग. ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो जो कि विधिक सेवाओं, स्कीमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विशेष रुचि रखता हो।

परिशिष्ट "क"

{नियम 7(2) और 8 (2) देखिये}

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	सचिव-दो	1	उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को अनुमन्य वेतनमान तदैव
2	विशेष कार्य अधिकारी	1	
3	उप सचिव	2	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को अनुमन्य वेतनमान
4	निजी सचिव	1	रु. 2000-60-230-द.रो.-75-3200
5	निजी सहायक	3	रु. 1640-60-2600-द.रो.-75-2900
6	आशुलिपिक	2	रु. 1200-30-1560-द.रो.-2040
7	प्रशासनिक अधिकारी	1	रु. 1640-60-2600-द.रो.-75-2900
8.	प्रवर वर्ग सहायक	3	रु. 1350-30-1440-40-1800-द.रो.-50-2200
9.	लेखा लिपिक	1	रु. 1200-30-1560-द.रो.-40-2040
10.	ज्येष्ठ लिपिक	1	रु. 1200-30-1560-द.रो.-40-2040
11.	टंकक	2	रु. 950-20-1150-द.रो.-30-1500
12.	कनिष्ठ लिपिक	3	रु. 950-20-1150-द.रो.-30-1500
13.	पुस्तकालय लिपिक	1	रु. 950-20-1150-द.रो.-30-1500
14.	अर्दली/चपरासी	10	रु. 750-12-870-द.रो.-14-940
15.	दफ्तरी मशीन आपरेटर	1	रु. 775-12-955-द.रो.-14-1025
16.	ड्राइवर	3	रु. 950-20-1150-द.रो.-30-1500
17.	सेवक	1	रु. 35.00 रुपये प्रतिदिन
18.	स्वीपर सह फर्शा	1	रु. 500.00 रुपये प्रतिमाह नियत वेतन

परिशिष्ट "ख"

{नियम 10 (2) और 8 (5) देखिये}

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	लिपिक	2	रु. 950-20-1150-द.रो.-30-1500
2.	अर्दली	2	रु. 750-12-870-द.रो.-14-940

परिशिष्ट "ग"

{नियम 12 (2) और 13 (2) देखिये}

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	लिपिक	66	रु. 950-20-1150-द.रो.-30-1500
2.	चपरासी	66	रु. 750-12-870-द.रो.-14-940

The Uttar Pradesh State Legal Services Authority hereby publishes the following English translation of notification no. 38/SLSA-104-97, dated September 11, 1997 for general information:

No. 38/SLSA- 104-97

Dated Lucknow, September 11, 1997

In exercise of the powers conferred by Section 29-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no. 39 of 1987) the Uttar Pradesh State Legal Services Authority hereby makes the following regulations:

**UTTAR PRADESH STATE LEGAL SERVICES
AUTHORITY (TRANSACTION OF BUSINESS
AND OTHER PROVISIONS)
REGULATION, 1997**

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

Short title and commencement

1. These regulations may be called the Uttar Pradesh State Legal Services Authority (Transaction) of Business and other Provisions) Regulations, 1997).
2. They shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette.

Definitions

2. In these regulations, unless the context otherwise requires-
 - a. "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987;
 - b. "General Authority" mean's the National Legal Services Authority constituted under section 3;
 - c. "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court;
 - d. "Court" means a Civil, Criminal or Revenue Court and includes any Tribunal or any other authority consituted under any law for the time being in force to exercise judicial of quasi-judicial functions;
 - e. "District Authority" means a District Legal Services Authority constituted under Section 9;

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय विभाग

अनुभाग-7

संख्या 38/एस.एल.एस.ए.- 104-97

लखनऊ, 11 सितम्बर, 1997

सा.प.नि.- 97

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) की धारा 29-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित विनियमावली बनाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997 कही जायेगी।
(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. इस विनियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) "अधिनियम" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 से है;
 - (ख) "केन्द्रीय प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से है;
 - (ग) "मुख्य न्यायमूर्ति" का तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से है;
 - (घ) "न्यायालय" का तात्पर्य कोई सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय से है और इसमें न्यायिक या न्यायिकेतर कृत्यों का प्रयोग करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी